



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 632) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
20 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-16/2009/1199—श्री शब्बीर अहमद, आई0 डी0 क्रमांक-3879, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई प्रमंडल संख्या-2, जमुई को इनके द्वारा एक सरकारी सेवक होने के उपरान्त पैक्स चुनाव 2009 में एक प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने, बोगस वोट डलवाने हेतु मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उच्चकागाँव थाना काण्ड संख्या-150/09 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा उक्त थाना काण्ड में दिनांक 16.10.2009 से 21.10.2009 तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 2916 दिनांक 27.11.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के उपनियम-2 के तहत न्यायिक हिरासत की अवधि (दिनांक 16.10.2009 से 21.10.2009 तक) के लिए निलंबित किया गया एवं उपनियम-3 (1) के तहत दिनांक 22.10.2009 से निलंबन से मुक्त किया गया।

2. श्री अहमद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई प्रमंडल संख्या-2, जमुई के विरुद्ध उक्त वर्णित आरोपों के लिए सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 09 दिनांक 05.01.2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर किये जाने के उपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया है परन्तु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1743/सी0 दिनांक 26.10.2009 से इनके विरुद्ध गठित आरोपों की पुष्टि होती है। फलस्वरूप प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-799 दिनांक 11.07.2013 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया:-

(i) निन्दन वर्ष 2009-10

(ii) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-799 दिनांक 11.07.2013 द्वारा संसूचित दण्ड के विरुद्ध श्री अहमद, सहायक अभियंता द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने पर पाया गया कि श्री अहमद, सहायक अभियंता को साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोपालगंज द्वारा वाद संख्या-जी0 आर0 2457/09, टी0 आर0 64/13 में दिनांक 30.10.2013 को पारित न्याय

निर्णय में दोषमुक्त कर दिया गया है जिससे प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के दिन ये मतदान केन्द्र पर नहीं गये थे तथा इन्होंने मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त श्री अहमद द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन में हवाला दिया गया कि ये आकस्मिक अवकाश लेकर घर गये थे एवं अपनी पत्नी को वोट दिलाने मतदान केन्द्र पर ले गये थे परन्तु इनके अवकाश आवेदन से स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी पत्नी की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण अवकाश का अनुरोध किया गया था। इनका उक्त कथन स्वयं विरोधाभासी है। फलस्वरूप उक्त आधार पर श्री अहमद का पुनरीक्षण अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 858 दिनांक 03.07.2014 द्वारा इनके पुनरीक्षण अभ्यावेदन को खारिज किया गया।

5. श्री अहमद द्वारा पुनः माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोपालगंज द्वारा वाद संख्या— जी0 आर0 2457/09, टी0 आर0 64/13 में दिनांक 30.10.2013 को पारित न्याय निर्णय जिसमें इन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है, की छायाप्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन, दिनांक 20.11.2014 विभाग में समर्पित किया गया तथा इनके निलंबन अवधि दिनांक 16.10.2009 से 21.10.2009 (कुल छः दिन) को विनियमित करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री अहमद के अभ्यावेदन दिनांक 20.11.2014 में उल्लिखित तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षा में यह पाया गया कि श्री अहमद द्वारा जिस न्याय निर्णय का उल्लेख उक्त अभ्यावेदन में किया गया है उसकी समीक्षा उनके पुनरीक्षण अभ्यावेदन में पूर्ण रूप से की जा चुकी है कि माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोपालगंज द्वारा वाद संख्या— जी0 आर0 2457/09 टी0 आर0 64/13 में दिनांक 30.10.2013 को पारित न्याय निर्णय से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के दिन ये मतदान केन्द्र पर नहीं गये तथा मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं किया।

किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा एवं विभागीय कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है एवं उक्त संदर्भ में विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर आरोप प्रमाणित पाते हुए इनके विरुद्ध दण्ड संसूचित किया गया तथा इनके पुनरीक्षण अभ्यावेदन को भी अस्वीकृत किया गया।

7. उक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर श्री अहमद के निलंबन की अवधि (कारावास की अवधि के लिए) दिनांक 16.10.2009 से 21.10.2009 तक के लिए निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होने एवं उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 632-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>